



वदिशी संप्रभु बाँण्ड

संदर्भ

2019-20 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने वदिशी संप्रभु बाँण्ड (Foreign sovereign bond) का जिक्र किया। इस बाँण्ड के माध्यम से सरकार द्वारा अपने सकल उधारियों का एक हिस्सा वदिशी बाज़ारों से प्राप्त करने का अनुमान व्यक्त किया गया है।

बाँण्ड क्या है?

- संप्रभु बाँण्ड सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों (Securities) होती है जिनके द्वारा सरकार राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) के वित्तीय तथा अस्थायी नकदी बेमेल (Temporary Cash Mismatch) का प्रबंधन करती है।
- यह रुपए अथवा वदिशी मुद्रा (डॉलर, आदी) में भी जारी किया जा सकता है। भारत में अभी तक सरकार ने केवल घरेलू बाज़ार में स्थानीय मुद्रा (रुपया आधारित) में ही संप्रभु बाँण्ड जारी किये हैं। हालाँकि अब भारत सरकार द्वारा वदिशी संप्रभु बाँण्ड वदिशी मुद्रा (डॉलर) में भी जारी किये जाएंगे।
- ऐसे निवेशकों के लिये मुद्रा स्थिरता महत्वपूर्ण होती है जो रुपए आधारित सरकारी बाँण्ड में निवेश करने का जोखिम उठाते हैं। ऐसी स्थिति में वदिशी संप्रभु बाँण्ड एक बड़ा अंतर उत्पन्न करते हैं। वदिशी मुद्रा (अधिकतर अमेरिकी डॉलर में) में जारी सरकारी बाँण्ड में मुद्रा जोखिम निवेशक से जारीकर्ता (सरकार) की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इस तरह के बाँण्ड के लेन-देन का नपिटारा यूरोक्लियर (Euroclear) पर किया जा सकता है, यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिभूति नपिटान प्रणाली है जो निवेश को वदिशी निवेशकों के लिये आसान बनाती है।

लाभ:

- अन्य उभरते बाज़ारों की तुलना में वैश्विक ऋण बाज़ार सूचकांकों (Global Debt Indices) में भारत का प्रतिनिधित्व काफी कम है। यह वैश्विक ऋण सूचकांकों में भारत के सरकारी बाँण्ड को शामिल करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे भारत में अधिक वदिशी धन की आवक हो सकेगी।
- भारतीय संप्रभु बाँण्ड के वैश्विक बेंचमार्क (Global Benchmarks) में शामिल होने से रुपए आधारित संप्रभु बाँण्ड (Rupee Denominated Sovereign Bonds) भी खरीदारों को आकर्षित कर सकेंगे।
- जसि दर पर सरकार वदिशों से संप्रभु बाँण्ड (Foreign Sovereign Bond) द्वारा उधार लेगी, वह अन्य कॉर्पोरेट बाँण्ड के मूल्य निर्धारण के लिये एक मानदंड (Yardstick) के रूप में कार्य करेगा, जसिसे भारत इंक को वदिशों से धन जुटाने में मदद मिलेगी।

हानियाँ:

- भारत द्वारा बाँण्ड के माध्यम से प्राप्त होने वाले वदिशी धन से देश के वदिशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी, इससे डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का अधिमूल्यन होगा जो आयात को प्रोत्साहित (जबकि सरकार आयात को नरियंत्रित करना चाहती है) करेगा जबकि निर्यात को हतोत्साहित (जबकि सरकार इसे प्रोत्साहित करना चाहती है) करेगा।
- डॉलर आधारित संप्रभु बाँण्ड वैश्विक ब्याज दरों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। ऐसे में यह भारतीय अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। वर्तमान में भारतीय ऋण में वदिशी निवेशकों की भागीदारी कम है, यह सरकारी प्रतिभूति का मात्र 3.6% है, जबकि इंडोनेशिया में यह 38% और मलेशिया में 24% है। इस संदर्भ में भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा आवश्यक प्रयास किये जा रहे हैं ताकि वदिशी निवेशकों के लिये निवेश की स्थिति को और आसान बनाया जा सकें।

घरेलू बाज़ार पर प्रभाव:

- इस प्रकार का कदम घरेलू बाज़ार में सरकारी बाँण्ड के प्रतिफल (Bond Yield) को कम कर सकता है जसिसे घरेलू, बचत, डाकघर जमाओं के ब्याज दरों में कमी आ सकती है।

यूरोक्लियर (Euroclear)

यूरोक्लियर एक बेलज़ियम-आधारित वित्तीय सेवा कंपनी (Financial Services Company) है जो प्रतिभूतियों के लेन-देन के नपिटान (Settlement of Securities Transactions) के साथ-साथ इन प्रतिभूतियों की सुरक्षा और परिसंपत्ति सेवाओं (Asset Servicing) में विशेषज्ञता रखती है।

स्रोत: द हट्टू

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/foreign-sovereign-bond>